

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण को लेकर की सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा- किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता।
- मुख्यमंत्री ने की नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा। कहा- प्रदेश में सौ वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों में अनिवार्य रूप से हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सात से पन्द्रह वर्ष तक के बच्चों के लिये आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क किया माफ। एक वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी यह व्यवस्था।
- प्रदेश के कई जिलों में रुक-रुक कर वर्षा का क्रम जारी। जन-जीवन हुआ प्रभावित। तेज हवा के साथ बारिश ने फसलों को पहुंचाया नुकसान।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नलकूपों से पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाए और वाटर कंजर्वेशन की समुचित व्यवस्था की जाए। एक रिपोर्ट....

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बाण सागर और मध्य गंगा जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा कर उसमें कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नलकूपों का प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता न किया जाए। मुख्यमंत्री ने तराई क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि रिजर्व वायर को डिसिल्ट कर उसे पुनर्जीवित किया जाए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेन्द्र त्रिपाठी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही लखनऊ में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि चेक डैम, तालाब और ब्लास्टकूप का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराएं। उन्होंने कहा कि जल संकट सामूहिक चिंता का विषय बन चुका है। चेक डैम, तालाब और ब्लास्टकूप वर्षा जल को रोककर धीरे-धीरे उसे भूमि में समाहित होने देते हैं। यह केवल स्थानीय प्राथमिकता नहीं है बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्षा जल संचयन और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सौ वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जिले में तालाबों, ब्लास्टकूपों और चेकडैमों की फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन कराएं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की बाइस तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। प्रस्तुत है कपड़ा क्षेत्र में टैक्स कटौती के प्रभाव पर हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।

आम आदमी को बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए, सरकार ने कपड़ा उद्योग पर जीएसटी कम कर दिया है। नई जीएसटी सुधारों के तहत, मानव निर्मित रेशों पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसी प्रकार, मानव निर्मित धागों पर भी जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके साथ ही, पच्चीस सौ रुपये प्रति पीस तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर भी जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे फैशन किफायती होगा और माँग में वृद्धि आएगी। जीएसटी टू प्वाइंट ओ के तहत यह शुल्किकरण मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए भारतीय परिधानों को किफायती बना देगा। रोहन के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संग्रह नियम-2008 में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार वैध और सक्रिय फास्टैग के बगैर टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन यदि नकद का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें आधिकारिक उपभोक्ता शुल्क का दो गुना भुगतान करना होगा। यदि शुल्क का भुगतान यूपीआई द्वारा किया जाता है तो आधिकारिक शुल्क का सवा गुना भुगतान करना होगा। यह नियम अगले महीने की पन्द्रह तारीख से लागू होगा।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सात से पन्द्रह वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि इस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क में छूट पहली अक्टूबर से लागू की गई है और एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस निर्णय से देश भर के लगभग छह करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एवं जौनपुर के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने कल जौनपुर में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों से मुलाकात कर जीएसटी कर सुधारों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों में कमी से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, बाजार को नई ऊर्जा मिलेगी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

बरेली में पिछली छब्बीस सितंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस अब तक तिरासी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि तौकीर रजा का मीडिया और संचार विभाग संभाल रहे मुनीर इदरीसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वस्तुस्थिति को देखते हुए बरेली और आसपास के जिलों में पुलिस हाई-अलर्ट पर है। बरेली में अब स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया है। वहीं पुलिस ने कल सुरक्षा के मद्देनजर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में सपा प्रतिनिधिमंडल को बरेली दौरे की अनुमति नहीं दी। सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा है कि बरेली में अब पूरी तरह अमन और चैन है।

प्रदेश में मिशन शक्ति का पांचवा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में ग्यारह अक्टूबर तक चलने वाले 'अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह' के अन्तर्गत कल प्रदेश भर में 'पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस' विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जोहरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह के अंतर्गत आयोजित यह कार्यक्रम बालिकाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक रिपोर्ट....

पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम के दौरान राज्य में जनपद, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर कार्यशालाएँ और सत्र आयोजित किये गये, जिनमें बालिकाओं और महिलाओं को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़े अधिकारों, उपायों और कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम का संचालन विषय विशेषज्ञों, समाजसेवियों और प्रशिक्षकों की उपस्थिति में हुआ। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार लखनऊ।

प्रदेश सरकार ने सात अक्टूबर को मनायी जाने वाली महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के कई जिलों में दो दिन पूर्व से रुक-रुक कर हो रही वर्षा के चलते जन-जीवन प्रभावित हुआ है। पूर्वी जिलों में तेज हवा चलने से बहुत से स्थानों पर पेड़ और बिजली के खम्भे गिर गये, जिससे आवागमन के साथ-साथ विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुयी। तेज हवा के साथ भारी बारिश से खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचा है। वाराणसी जिले में रिकॉर्ड वर्षा हुयी है। वहां पिछले एक सौ पचीस वर्षों में अक्टूबर में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड कायम हुआ है। एक रिपोर्ट—

मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक वाराणसी में 125 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले वर्ष 1900 में 138.9 मिमी बारिश हुई थी। बीएचयू स्थित मौसम स्टेशन में 9 अक्टूबर 1900 को एक दिन में 138.9 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मनीष सिंह आकाशवाणी समाचार वाराणसी।

गोरखपुर सहित कई जिलों में आसमान में आज सुबह से ही घने बादल छाये हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा की वायुमण्डलीय परिस्थितियां अभी भी बनी हुयी हैं, जिसके चलते अगले चौबीस से अड़तालीस घंटे तक रुक-रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है।
